एक नजर में

अन्ना को किया तड़ीपार

नागपुर, नगर प्रतिनिधि. जोन-3 के पुलिस उपायुक्त राहुल मदने ने कई संगीन मामलों में नामजद अपराधी मोमिनपुरा निवासी मोहम्मद अजनान उर्फ अन्ना मोहम्मद नियाज (20) को एक वर्ष के लिए नागपुर शहर और ग्रामीण सीमा से एक वर्ष के लिए तड़ीपार करने का आदेश जारी किया. अजनान पर तहसील थाना क्षेत्र में घातक हथियार से हत्या का प्रयास, मारपीट, जानलेवा शस्त्रों से हमला करना जैसे मामले दर्ज हैं. उसकी लगातार बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए डीसीपी मदने ने यह आदेश जारी किया.

नकदी समेत 1.29 लाख का माल उड़ाया

नागपुर, नगर प्रतिनिधि. कलमना थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाकर 1 लाख रुपये नकद और होम थियेटर, लैपटॉप आदि समेत 1,29,800 रुपये के माल पर हाथ साफ कर दिया. जानकारी के अनुसार, गुलशननगर निवासी सुनील नारायण सायरे (52) घर पर ताला लगाकर परिवार के साथ अपने जरीपटका निवासी बड़े भाई के यहां रहने के लिए गए हुए थे. इसी बीच किसी अज्ञात चोर ने मेन डोर का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया और बेडरूम की अलमारी में रखे एक लाख रुपये के अलावा होम थियेटर, एलसीडी टीवी, तेल का डिब्बा, लैपटॉप आदि समेत 1,29,800 रुपये का माल चोरी कर लिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.

वाहन खरीदी ः आफर के नाम पर 6.55 लाख की धोखाधड़ी

नागपुर, नगर प्रतिनिधि. बजाजनगर थानाक्षेत्र में इलेक्ट्रिक स्कूटर विक्रेताओं द्वारा स्टूडेंट आफर के तहत कीमत में छूट देने के बहाने 9 लोगों से 6.55 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया. आरोपियों के नाम रामनगर, वर्धा निवासी गणेश बच्चुमल पंजवानी (46) और अनिल राजकुमार वलिच्छा (48) बताये गये हैं. जानकारी के अनुसार, पंजवानी और वलिच्छा, दोनों दीवान प्लाजा, रामदासपेठ में इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने की दूकान चलाते हैं. क्रेटा कालोनी निवासी भोलेशंकर चेतनदास कस्तुरी (55) निवासी ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि जब वे इस दूकान में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने पहूंचे तो दोनों आरोपियों ने उन्हें बताया कि कंपनी में स्टूडेंट के लिए आफर चल रहा है. यदि कोई स्टूडेंट आफर के तहत स्कूटर खरीदी करेगा तो उसे कीमत में छूट दी जायेगी. झांसे में आकर भोलेशंकर ने अपने अलावा अन्य 9 रिश्तेदारों को भी उक्त इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने के लिए मनाया. आरोपियों ने सभी से बुकिंग अमाउंट ले लिया लेकिन स्कूटर नहीं दी. इसी प्रकार आरोपियों ने कुल 22 लोगों से 6.55 लाख रुपये की ठगी की जिसमें बुकिंग अकाउंट देने के बावजूद इलेक्ट्रिक स्कूटर डिलीवर नहीं की. भोलेशंकर की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

शासकीय बालक हाई स्कूल के छात्रों ने मारी बाजी

सारनी। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र विसंत पंडागरे ने दसवीं बोर्ड परीक्षा में 92.20 अंक प्राप्त कर जिले की टॉप टेन सूची में स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा छात्र अभिषेक खरे ने 88.60 अंक .कार्तिक उईके ने 84.00 अंक .छात्र तरुण यादव ने 82.80 अंक तथा छात्र फैजान खान ने 76.30 अंक प्राप्त किये है। बालक हाई स्कूल की प्राचार्य श्रीमती सरिता झरबडे ने बताया कि 10 बोर्ड परीक्षा में विद्यालय के छात्रों ने बाजी मारी है. बताया जाता है कि इस वर्ष विद्यालय का बोर्ड परीक्षा परिणाम कक्षा 10 वीं का 60 प्रतिशत एवं कक्षा 12 वीं का 67 प्रतिशत रहा है।

डिजिटल सिस्टम बनाने वाले ने ही किया 'हैक'

रेत तस्करी में माफियाओं ने किए 200 करोड़ से अधिक के वारे-न्यारे

- 3.50 लाख रुपये महीना एक वाहन से बंधी है 'देन'
- 8 ब्रास रेत भरी जाती है 5 ब्रास क्षमता वाली गाड़ियों में
- 150-200 ट्रक रोज लोड हो रहे कन्हान के नेरी घाट से

नागपुर, निज संवाददाता. आम नागरिकों को सस्ते दाम पर रेत उपलब्ध कराने का पूरा सरकारी सिस्टम ही फेल हो गया है. इसे फेल किया है सिस्टम के ही नुमाइंदों ने. राज्य सरकार ने आम नागरिकों को सस्ती दर पर रेत उपलब्ध कराने के लिए ?600 रुपए प्रति ब्रास की दर पर रेत देने की नीति वर्ष 2023 में लागू की थी. इसका मुख्य उद्देश्य घर निर्माण लागत कम करना, अवैध रेत खनन रोकना और आम जनता को पारदर्शी तरीके से रेत उपलब्ध कराना था. यह नीति आम नागरिकों को सस्ती रेत उपलब्ध कराने और रेत माफिया व काला बाज़ारी पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से बनाई गई थी. रेत घाटों में गाड़ी पहुंचने, लोड होने और उसके निर्धारित गंतव्य तक पहुंचने की निगरानी के लिए पुणे की एक कंपनी को ठेका दिया गया जिसने डिजिटल सिस्मट तैयार किया. सूत्र की मानें तो इस सिस्टम को बनाने वाले ने ही इसे 'हैक' कर लिया. अपने मूल उद्देश्य को छोड़कर उसने रेत माफियाओं व संबंधित यंत्रणा को 'सेट' कर वारे-न्यारे शुरू कर दिये. रेत चोरी रोकने का सिस्टम ही कमाई का जरिया बना लिया गया. बताया जाता है कि अकेले नागपुर के विविध रेत घाटों पर सैकड़ों वाहन लोड हो रहे हैं. अवैध उत्खनन व ढुलाई वाले एक वाहन से 3.50 लाख रुपये महीने की 'देन' वसूली जाती है. अगर ऐसे 500 वाहन भी पकड़ें तो 17.50 करोड़ रुपये महीने का चूना लगाया जा रहा है. वर्षभर में यह 210 करोड़ रुपये होता है.

चिखली, बुलढाना की मारते हैं रायल्टी

सूत्र ने दावा किया कि कन्हान नदी के नेरी घाट से रोज 150 से 200 वाहन भरे जा रहे हैं लेकिन रायल्टी चिखली, बुलढाना की मारते हैं. इतना ही नहीं वाहनों में उसकी क्षमता से अधिक रेत लोड की जा रही है. 5 ब्रास की क्षमता वाले ट्रकों में 8-8 ब्रास रेत भरी जाती है. इसका तो हिसाब ही नहीं है. कितने ट्रक किस घाट पर पहुंचते हैं, ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम से तत्काल संबंधित विभाग के अधिकारी को जानकारी मिल जाती है. मगर लोड होने वाले वाहनों की संख्या कहीं कम दर्शाई जाती है. कितनी चोरी किस घाट से हो रही है सबको पता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती. कभी शिकायत हो गई तो छुटपुट कार्रवाई की जाती है.

वाट्सएप ग्रुप से अधिकारियों को किया जाता है 'ट्रेक'

माफिया इतने शातिर हैं कि घाट से निकलते ही वाहन के जीपीएस सिस्टम को बंद कर देते हैं, ताकि रूट का पता न चल सके. बावजूद ऐसे वाहनों की ओर देखा तक नहीं जाता. अगर कोई अधिकारी कार्रवाई करने भी निकले तो विभाग के 'विभीषण' उसकी सूचना संबंधित को दे देते हैं. सूत्र ने दावा किया कि रेत तस्करी में लगे माफियाओं के 8 से 10 वाट्सएप ग्रुप हैं. हर ड्राइवर इन ग्रुप में जुड़े हैं. कार्रवाई करने निकलने वाले अधिकारी को ट्रेक कर उसकी लोकेशन तक वायरल कर दी जाती है. इससे अधिकारी की जान को भी खतरा है. खनिकर्म व राजस्व विभाग के अनेक अधिकारियों पर वाहन चढ़ाकर हत्या करने या फिर हत्या का प्रयास करने की कई घटनाएं हो चुकी हैं. यह साइबर क्राइम है और ऐसे वाट्सएप ग्रुप की जांच कर एडमिन को गिरफ्तार किया जाना चाहिए.

इसलिए महंगी पड़ती है रेत

पहले सेपरेट घाट की नीलामी होती थी. अब तहसील-वार मतलब एक तहसील में जितने घाट हैं उन्हें एक साथ क्लब कर नीलाम किया जाता है. जिस घाट में रेत नहीं निकलती वह भी इसमें शामिल होता है. इससे घाट का ठेका लेने वाले को रेत महंगी पड़ती है, जबकि सरकार रेत सस्ती उपलब्ध कराने का दावा करती है.

पक्ष व विपक्ष सभी हैं शामिल

बिना राजनीतिक संरक्षण के इतने बड़े पैमाने पर गौण खनिज का अवैध उत्खनन व परिवहन हो ही नहीं सकता. चाहे फिर वह सत्ताधारी हों या विपक्ष के कर्णधार. अपने-अपने इलाके में इन्हें माफियाओं से मोटी रकम पहुंचाए जाने का दावा भी सूत्र ने किया है. रेत तस्करी में वर्चस्व की लड़ाई में नागपुर सहित अनेक जिलों में हत्याएं भी हो चुकी हैं. कुछ ऐसे माफियाओं के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है जिनके संबंध सीधे राजनीतिक पार्टी व इलाके के दिग्गज नेताओं के साथ हैं.

आईटी, ईडी भी मूकदर्शक

गौण खनिजों में रेत सबसे महत्वपूर्ण है और यह रेत माफियाओं के लिए सोना बन गया है. इसकी तस्करी में जुटे छुटभैय्ये भी मालामाल हो चुके हैं. सरकारी तंत्र में शामिल विभागों के जो कर्णधार माफियाओं से मिले हुए हैं उनकी तो उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में है. इस गोरखधंधे में जुटे लोग 2-3 वर्षों में ही इतना 'पीट' चुके हैं अब लक्जरी वाहनों में नजर आते हैं. कई बार दिखावे की छोटी-मोटी कार्रवाइयां भी होती हैं. आश्चर्य की बात यह भी है कि बेहिसाब नंबर दो की कमाई करने वाले माफियाओं की ओर से आईटी और ईडी विभाग भी मूकदर्शक बना हुआ है.

ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा के लिए 'एफआरपी' का कवच

अंततः महावितरण ने उठाया कदम, हादसों व चोरी पर लगेगा नियंत्रण

नागपुर, निज संवाददाता. महावितरण ने अब अपने ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा के लिए फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीइथिलीन (एफआरपी) की बाड़ लगाने का निर्णय लिया है. इससे ट्रांसफार्मरों से ऑयल की चोरी के साथ ही करंट लगने जैसी दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी. यह सुरक्षा की बाड़ शॉकप्रूफ होगी. बता दें कि पड़ोसी राज्यों में बिजली कंपनियों द्वारा अपने हर ट्रांसफार्मर परिसर को लोहे की बाड़ से घेरा जाता है लेकिन यहां इसका अभाव था. अब

कंपनी जागी है. अक्सर बिजली वितरण ट्रांसफॉर्मरों के दरवाजे खुले रहने या जंग लगकर टूट जाने के कारण नागरिकों, विशेषकर खेलते हुए छोटे बच्चों और राहगीरों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है. इस संभावित जोखिम को देखते हुए महावितरण ने उक्त निर्णय लिया. यह एफआरपी कोटिंग न केवल सुरक्षित है, बल्कि बारिश, तेज धूप और सर्दी जैसे सभी प्रकार के मौसमी बदलावों को सहन करने में भी सक्षम है. कई स्थानों पर ट्रांसफार्मर के आसपास लोग कचरा फेंक देते हैं, जिससे वहां टेक्नीशियन्स के लिए कार्य करना कठिन और जोखिमपूर्ण हो जाता है. इस कचरे से फैलने वाली दुर्गंध से स्थानीय निवासियों को भी परेशानी होती है. यदि कोई इस कचरे में आग लगा दे, तो उसकी चपेट में बिजली यंत्रणा आकर भारी आर्थिक नुकसान या भीषण दुर्घटना हो सकती है.

1000 स्थानों पर लगेंगे बाड़

बताया गया कि आने वाले 24 महीनों में इस संपूर्ण परियोजना का कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा. पहले चरण में नागपुर जिले के 900 और वर्धा जिले के 100 ट्रांसफॉर्मरों पर सुरक्षा कवच लगाया जाएगा. परिसर में महावितरण द्वारा पारदर्शिता के लिए प्रत्येक केंद्र का वितरण ट्रांसफॉर्मर क्रमांक, संबंधित क्षेत्र के जिम्मेदार जनमित्र का नाम, उनका मोबाइल नंबर तथा उस ट्रांसफॉर्मर की बिजली वितरण हानि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी वाला बोर्ड भी लगाया जाएगा. इससे आपातकालीन स्थिति या तकनीकी शिकायत होने पर नागरिक सीधे और तुरंत महावितरण से संपर्क कर सकेंगे.

AC वेटिंग रूम नई इमारत में शिफ्ट

स्टेशन (पश्चिमी भाग) ः पुरानी इमारत खाली करने की कवायद शुरू

नागपुर, नगर प्रतिनिधि. देश के सबसे प्रमुख और व्यस्त स्टेशनों में शामिल नागपुर स्टेशन का पुनर्निर्माण तेज गति से जारी है. रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (आरएलडीए) द्वारा 487.77 करोड़ की लागत से यह परियोजना पूरी की जा रही है. प्लेटफॉर्म 2 के नवीनीकरण शुरू होने के बाद पश्चिमी भाग में स्थित एसी वेटिंग रूम यानी उच्च श्रेणी वातानुकूलित प्रतीक्षालय भी प्लेटफॉर्म 1 के इटारसी छोर पर बनी नई इमारत में शिफ्ट कर दिया गया है. वहीं इस ओर हेरिटेज इमारत से लगी स्टेशन की दूसरी इमारत को खाली करना शुरू कर दिया गया है. हालांकि कुछ पेंच अब भी फंसे हुए हैं.

शौचालयों में नहीं नहाने की सुविधा

0 ज्ञात हो कि जिस इमारत में एसी वेटिंग रूम शिफ्ट किया गया है, वास्तव में यहां नया डीआरएम ऑफिस स्थापित किया जाना है लेकिन स्टेशन पर हो रहे पुनर्निर्माण के चलते यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए एसी वेटिंग यहां शिफ्ट किया गया है.

0 यहां करीब 4 से 8 कमरे यात्रियों के बैठने के लिए उपलब्ध कराये गये हैं. महिला वेटिंग रूम भी अलग कमरे में बनाया गया है.

0 पूर्णतः वातानुकूलित इस इमारत में हैंड ड्रायर जैसी सुविधायुक्त टॉयलेट बनाये गये हैं लेकिन यात्रियों ने शिकायत की कि नहाने की कोई सुविधा नहीं है, जबकि पुराने एसी वेटिंग रूम में यह सुविधा थी.

0 लंबे सफर से आने के बाद दूसरे सफर से पहले यात्रियों को नहाने की आवश्यकता महसूस होती है लेकिन नये

वेटिंग रूम के शौचालयों में ऐसी सुविधा न होने से उन्हें मायूस होना पड़ रहा है.

शिफ्टिंग पर जारी खींचातानी

ज्ञात हो कि जिस इमारत को खाली करना है वहां एसी वेटिंग रूम के अलावा रेलवे सुरक्षा बल थाना, क्लार्क रूम, टिकट चेकिंग स्टाफ ऑफिस, क्लीनिक, रेस्ट रूम, बेस किचन आदि हैं लेकिन किन्हीं स्थितियों के चलते इस इमारत को खाली करने में समय लग रहा है. सूत्रों के अनुसार, बेस किचन पहले ही बंद किया जा चुका है. अभी टिकट चेंकिंग स्टाफ ऑफिस और आरपीएफ पोस्ट को भी प्लेटफॉर्म 1 पर बनी नई इमारत में ही शिफ्ट किया जा रहा है लेकिन टिकट चेकिंग स्टाफ के लिए यहां बड़े कमरे की मांग है. इस मांग के लिए मंडल प्रबंधन ने पूर्वी भाग में बनी नई इमारत में व्यवस्था का सुझाव दिया तो मांग की जा रही है कि कि उक्त ऑफिस प्लेटफॉर्म 1 पर ही होना चाहिए. लेकिन मांग अनुरूप आकार का हाल या कमरा नहीं है. दूसरी तरफ आरपीएफ के लिये यहां 4 या 5 कमरे दिये गये हैं लेकिन लॉकअप सुविधा न होने से उन्हें भी शिफ्ट करने में देर हो रही है. ऐसी ही वजहों से हेरिटेज इमारत से लगी उक्त इमारत जल्द से जल्द खाली नहीं हो पा रही है.

11 दिसंबर 2022 ः परियोजना का शिलान्यास
487.77 करोड़ ः कुल लागत
36 महीने ः पहली डेडलाइन
12 महीने ः डेडलाइन में बढ़ोतरी

बिरसा मुंडा और डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा की होगी स्थापना

मुलताई। प्रभात पट्टन ब्लॉक के ग्राम माझरी में बिरसा मुंडा एवं डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। जिसे लेकर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रामनगर मे भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित करने पांच कन्याओं के शुभ हाथों से युवा समाजसेवी लोकेश गीदकर द्वारा पूजा-अर्चना कर भूमिपूजन किया गया। इसके बाद ग्राम माझरी के मुख्य चौक पर डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना हेतु भी विधिवत पूजा कर भूमि पूजन संपन्न किया गया।कार्यक्रम मे जनपद सदस्य प्रीति उइके, सरपंच बिलसु पन्द्राम सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे। सरपंच बिलसु पन्द्राम ने बताया लोकेश गीदकर अपने जन्मदिन के अवसर पर दोनों प्रतिमाएं भेंट कर रहे हैं, साथ ही प्रतिमा स्थापना हेतु पेडस्टल निर्माण की जिम्मेदारी भी स्वयं निभाएंगे। इस सराहनीय पहल के लिए ग्रामवासियों ने उनका आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकेश गीदकर ने कहा समाज में आपसी सहयोग और भाईचारा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आदिवासी समाज हमारी जड़ है और हमें आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य देना हमारा कर्तव्य है।

महज 8 घंटे में आवेदन को मिलेगी मंजूरी

सीएम सहायता निधि की नई ऑनलाइन प्रणाली जल्द

2,320 मरीजों का इलाज जिले में 19.79 करोड़ की मदद

नागपुर, महानगर संवाददाता. राज्य के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए मुख्यमंत्री सहायता निधि एवं धर्मादाय अस्पताल सहायता कक्ष की नई अत्याधुनिक ऑनलाइन प्रणाली जल्द शुरू होने जा रही है. इस प्रणाली के लागू होते ही मरीजों को आर्थिक सहायता मिलने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी और आवेदन मंजूरी महज 8 घंटे में पूरी की जाएगी.

मुख्यमंत्री सहायता निधि कक्ष के प्रमुख एवं सदस्य सचिव डॉ. सागर पांडे ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत अब मरीजों को स्वयं आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी. कक्ष से संबद्ध अस्पताल ही मरीज के दस्तावेज लेकर सीधे आवेदन प्रस्तुत करेंगे जिससे उपचार प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होगी. इस नई प्रणाली का उद्घाटन जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों किया जाएगा. मरीज द्वारा अस्पताल में सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद अस्पताल प्रशासन आवेदन को मंजूरी के लिए भेजेगा और सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर 8 घंटे के भीतर स्वीकृति मिल जाएगी. आर्थिक वर्ष अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के दौरान राज्य में कुल 40,776 मरीजों को 333 करोड़ 6 लाख 81 हजार 500 रुपये की सहायता प्रदान की गई. वहीं नागपुर जिले में 2,320 मरीजों को 19 करोड़ 79 लाख रुपये की मदद दी गई.

– कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए विशेष पहल: मुख्यमंत्री सहायता निधि कक्ष, बीपीसीएल फाउंडेशन और टाटा मेमोरियल सेंटर के बीच बच्चों के कैंसर उपचार के लिए समझौता किया गया है. इसके तहत सीएसआर फंड के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराया जाएगा. नागपुर जिले में पिछले वर्ष 'नमो नेत्र संजीवनी शिविर', 'आरोग्याचा श्री गणेशा' सहित कुल 747 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए जिनमें 53,422 मरीजों ने लाभ प्राप्त किया. अधिक जानकारी के लिए जरूरतमंद मरीज 1800 123 2211 टोल-फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.

टीकाकरण के महत्व को आमजन को समझना होगा

बैतूल। महिला एवं बाल विकास विभाग जिला, स्वास्थ्य विभाग जिला, नगर पालिका परिषद द्वारा संयुक्त रूप से नगर पालिका बाल मंदिर सभा कक्ष में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम अंतर्गत स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार महिलाओं के महिलाओं के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका उपाध्यक्ष महेश राठौर एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी सोमनाथ राय द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर अंतर्गत स्वयं स्वास्थ्य जांच कराई जाकर कार्यक्रम में सम्मिलित आमजनों को शिविर में भाग लेकर इसे सफल बनाने हेतु प्रोत्साहित किया गया। शिविर में स्वास्थ्य जांच कर आवश्यकतानुरूप काउंसलिंग की गई। श्री राय द्वारा शासन की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आमजनों के लिए उपलब्ध महत्वपूर्ण सुविधाएं जैसे समाज के कमजोर और लोक अदालतों के माध्यम से मामलों का त्वरित निपटान की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई।

स्वच्छता की पाठशाला का किया आयोजन

बैतूल। नगर पालिका परिषद बैतूल की स्वच्छता टीम द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के अंतर्गत आज नगर पालिका सीएमओ नवनीत पांडे के निर्देशन में नगर के एलएफएस स्कूल में स्वच्छता की पाठशाला का आयोजन किया गया जिसमें स्वच्छता की ब्रांड एंबेसेडर श्रीमती नेहा गर्ग, स्वच्छता निरीक्षक संतोष धनेलिया, स्कूल मैनेजमेंट स्टाफ, क्लास टीचर, ओम साई विजन टीम एवं बच्चे उपस्थित रहे। पाठशाला में स्वच्छता निरीक्षक श्री धनेलिया ने बच्चों को स्वच्छता की जानकारी दी। गीले एवं सूखे कचरे की जानकारी दी। श्रीमती नेहा गर्ग ने घरों से निकलने वाले कबाड़ को कैसे पुनः उपयोग किया जाए कि जानकारी दी और स्वयं के निवास पर कबाड़ से बनाए गए विभिन्न गमलों में पौधे लगाने के बारे में बताया और यह भी बताया कि ऐसी छोटी-छोटी चीजों का उपयोग कर आप अपने घर में भी रख सकते हैं। स्कूल के वरिष्ठ व्याख्याता जीपी भट्ट ने अपने उद्बोधन में स्वच्छता को लेकर शाला के विद्यार्थियों को कई जानकारी दी और शाला प्रांगण और अपने घर को भी स्वच्छ रखने की भी अपील की है। कार्यक्रम के अंत में सभी ने स्वच्छता की शपथ ली कि सभी अपने आस पास स्वच्छता बनाए रखेंगे।

कलेक्टर श्री वशिष्ठ ने सहपरिवार किया जैविक ग्राम भुम्मा का भ्रमण

जैविक खेती, बॉयोगैस और होम स्टे की संभावनाओं से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता भुम्मा गांव

नव भारत न्यूज

पांढुरना, 17 अप्रैल, जैविक कृषि एवं ग्रामीण आत्मनिर्भरता का उत्कृष्ट उदाहरण बन रहे पांढुर्णा जिले के ग्राम भुम्मा का, कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ द्वारा सहपरिवार भ्रमण किया गया। जहां हर घर में पशुधन एवं बॉयोगैस की उपलब्धता है, वहीं अब इस जैविक ग्राम में होम स्टे विकसित करने की दिशा में भी पहल की जा रही है।

आज दिनांक 17 अप्रैल 2026 को कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ द्वारा सहपरिवार ग्राम भुम्मा पहुंचकर किसान मटरूलाल डोंगरे के प्रक्षेत्र में हो रही जैविक हल्दी की खेती एवं प्रोसेसिंग यूनिट का भ्रमण किया। उन्होंने प्राकृतिक खेती की प्रक्रिया की जानकारी ली। मटरूलाल डोंगरे ने बताया कि उनकी जैविक हल्दी आस्ट्रेलिया, पेरिस एवं जापान तक निर्यात हो रही है और वे अन्य किसानों को भी इस दिशा में प्रेरित कर रहे हैं।

कलेक्टर श्री वशिष्ठ ने गांव के किसानों द्वारा किए जा रहे नवाचारों की सराहना करते हुए सभी किसानों को समूह में हल्दी उत्पादन कर मार्केट लिंकेज के माध्यम से सामूहिक रूप से विक्रय करने के लिए प्रेरित किया, जिससे

किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके। साथ ही, ग्राम भुम्मा की प्राकृतिक सुंदरता एवं जामसांवली तथा अर्द्धनारिश्वर मंदिर के समीप स्थित होने को ध्यान में रखते हुए गांव में होम स्टे निर्माण करने का सुझाव दिया, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर प्राप्त हो सकें।

ग्राम भुम्मा में लगभग 230 परिवार निवासरत हैं, जिनमें लगभग सभी परिवारों के पास पशुधन उपलब्ध है तथा करीब 85 प्रतिशत परिवार घरेलू उपयोग में बॉयोगैस का उपयोग कर रहे हैं। इससे गांव के किसान एलपीजी गैस पर निर्भर नहीं हैं। साथ ही, बॉयोगैस संयंत्र से निकलने वाली खाद का उपयोग खेतों में किया जा रहा है।

भ्रमण के दौरान कलेक्टर श्री वशिष्ठ ने किसान श्री धनवत गोहिते के प्रक्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मूंगफली, मूंग, मक्का, गोभी एवं बॉयोगैस संयंत्र का अवलोकन किया तथा कृषक श्री प्रहलाद गोहिते के खेत में तरबूज की खेती का भी निरीक्षण किया।

इस अवसर पर उप संचालक कृषि जितेन्द्र कुमार सिंह ने किसानों से जैविक खेती पर चर्चा की और मटरूलाल डोंगरे के कार्यों की सराहना करते हुए किसानों से प्राकृतिक उत्पादों को जैविक हाट बाजार में उपलब्ध कराने की अपील की।

भ्रमण के दौरान सहायक संचालक कृषि दीपक चौरसिया, कृषि विस्तार अधिकारी पंकज पराडकर, कैलाश चुर्वे, दिलीप परतेती, ब्लॉक टेक्नॉलाजी मेनेजर सुभाष साहू, असिस्टेंट टेक्नॉलाजी मेनेजर श्रीमती दीपिका गायकवाड़ सहित ग्राम के समस्त प्रगतिशील किसान उपस्थित रहे।

संदीपनि-उत्कृष्ट विद्यालयों का बेहतर समन्वय, विद्यार्थियों को मिलेगा व्यापक लाभ

कलेक्टर के सक्रिय प्रयासों से पांढुर्णा में शिक्षा व्यवस्था सशक्त, सीटों में ऐतिहासिक वृद्धि

नव भारत न्यूज

पांढुरना, 17 अप्रैल, जिला मुख्यालय पांढुर्णा में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ द्वारा सराहनीय पहल की गई है। शासकीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए पालकों की लगातार बढ़ती मांग को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर जिला पांढुर्णा ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। शैक्षणिक सत्र 2026 में विद्यार्थियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि तथा भवन व्यवस्था में व्यापक सुधार सुनिश्चित किया गया है। 8 अप्रैल 2026 को आयोजित बैठक के उपरांत कलेक्टर श्री वशिष्ठ के मार्गदर्शन में

कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ

निम्नलिखित व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से लागू की गई हैं—

हायर सेकेंडरी (कक्षा 11वीं एवं 12वीं) के लिए प्रमुख पहल

सीटों में वृद्धि: कलेक्टर श्री वशिष्ठ के निर्देशानुसार कक्षा 11वीं एवं 12वीं में पूर्व स्वीकृत 240-240 सीटों के स्थान पर अब 320-320 सीटें निर्धारित की गई हैं, जिससे प्रति कक्षा 8 सेक्शन संचालित होंगे और अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश का अवसर मिलेगा।

भवन व्यवस्था: संदीपनि विद्यालय के नवीन भवन के 12 में से 10 कक्ष विज्ञान संकाय के लिए तथा पुराने उत्कृष्ट विद्यालय भवन के 8 कक्ष वाणिज्य एवं कला संकाय के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार कुल 20 कक्षों में सुव्यवस्थित रूप से कक्षाओं का संचालन किया जाएगा।

माध्यमिक एवं प्राथमिक स्तर पर प्रभावी व्यवस्था

प्रवेश प्रक्रिया: कलेक्टर श्री वशिष्ठ के स्पष्ट निर्देशों के तहत कक्षा 6वीं में रिक्त 32 सीटों एवं कक्षा 7वीं में रिक्त 19 सीटों पर शीघ्र प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराई जा रही है। कक्षा 9वीं में रिक्तियों की स्थिति पूरक परीक्षा परिणाम के बाद स्पष्ट होगी।

शालाओं का संविलियन: लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशों के अनुरूप, कलेक्टर श्री वशिष्ठ के नेतृत्व में संदीपनि विद्यालय में रिक्त 329 सीटों की पूर्ति के लिए शासकीय प्राथमिक शाला गांधी, रामचंद्र एवं इंदिरा पांढुर्णा का संदीपनि विद्यालय में संविलियन किया गया है। प्राथमिक कक्षाओं के संचालन के लिए 28 कक्षों की समुचित व्यवस्था की गई है।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

कलेक्टर श्री वशिष्ठ द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि पुराने उत्कृष्ट विद्यालय भवन में शेष बचे कक्षों का उपयोग शिक्षक प्रशिक्षण एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए किया जाए। साथ ही, विकास खंड शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित प्राचार्यों को इन व्यवस्थाओं को तत्काल प्रभाव से लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कलेक्टर श्री वशिष्ठ की इस पहल से क्षेत्र के सैकड़ों विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा, जो अब तक सीमित सीटों के कारण प्रवेश से वंचित रह जाते थे।